Mr. Speaker: I have seen it. Mr. Madhu Limaye also wrote to me yesterday or day before yesterday. Some other Members also—I do not remember all the names of other Members—have given notice of adjournment motions and so many other things to find out whether anything has been done, as to who is in the pay-roll of Birlas and all that. I cannot give a decision off-hand. I am allowing a Call Attention Notice tomorrow and, I think, they will be able to give some information.

Shri H. N. Mukerjee: We have the right to have a full-fledged discussion.

Mr. Speaker: That is a different matter. If you want to have a full-fledged discussion, you will have to adopt some other method. The Call Attention Notice gives only the privilege of putting a question to a few Members. I can call only those whose names have been put on the list. But, for the present, I have admitted it as a call-attention because it cannot be a privilege motion.

Shri H. N. Mukerjee: My submission is....

Mr. Speaker: It is now done. Tomorrow, we shall discuss, not now. I have called Mr. Devgun.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रिविलेज के बारे में अर्ज कर रहा हूं।

Mr. Speaker: I would not allow anything on that subject. That is a subject which I have taken a decision now.

श्री मधु लिमये : ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव तो अलग बात है न।

Mr. Speaker: He can discuss in the chamber, not here.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I have another submission to make. I am not saying anything about that call-attention; this has nothing to do with that call-attention. My submission is that you agreed in this House.

Mr. Speaker: I have called Mr. Devgun and he is on his legs. How can Mr. Banerjee say now that he wants to raise something else?

Mr. Devgun.

12.52 hrs.

MOTION RE. FIRST REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विशेषाधिकार समिति के पहले प्रतिवेदन पर, जो 12 मई, 1957 को सभा में पेश किया गया था, विचार किया जाये।"

Mr. Speaker: Just a minute. Only half an hour is allowed for this. We should finish it within half an hour—ten minutes now and about fifteen minutes after Lunch.

श्री हरदयाल देवगुण : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आप को और इस सदन को मालूम है, इस सदन के एक माननीय सदस्य स्वामी ब्रह्मानन्द जी, को 5 अप्रैल को संसद् भवन के सामने गिरफ्तार किया गया, परन्तु उस की सूचना जिला अधिकारियों ने आप को और इस सदन को नहीं दी। सदन के नियम 229 और 230 के अनुसार इस बारे में इस सदन को और आप को इस की सूचना मिलनी चाहिए थी, परन्तु यहां के जिला अधिकारी इस कर्त्तव्य में असफल रहे। इसलिए 7 अप्रैल को यहां पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया।

उस अवसर पर वक्तव्य देते हुए गृह-मंत्री जी ने कहा कि स्वामी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि वह स्वयं गिरफ्तार हुए। उन्होंने यह भी कहा कि वह जो वक्तव्य दे

[श्री हरदयाल देवगुण]

रहे हैं, वह उस की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।

उस के बाद यह मामला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया गया और उस का प्रतिवेदन 22 मई को इस सदन के पटल पर रखा गया। उस प्रतिवेदन से दो बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जिला अधिकारियों की असफलता को छिपाने और उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। प्रतिवेदन में साफ कहा गया है कि उस दिन स्वामी जी को गिरफ्तार किया गया और उन को एक प्रकार से 3 बजे से ले कर 7 बजे तक थाने में रखा गया पर जिन हालात में उन को वहां पर रखा गया, उस को नजरबन्दी के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता है।

उस प्रतिवेदन में दूसरी बात यह कही गई है कि नियमों के अनुसार जिला अधिकारियों को उस गिरफ्तारी की सूचना आप को और इस सदन को देनी चाहिए थी, लेकिन वह इस में असफल रहे हैं।

विशेषाधिकार समिति की सारी कार्यवाही और उस के निष्कर्षों को पढ़ने से कुछ प्रश्न बड़े गम्भीर रूप से हमारे सामने आते हैं। जैसा कि मैं ने कहा है, गृह मंत्री जी ने तथ्यों को जांच किये बगैर इस सदन में कहा कि जो कुछ मेरा अफसर कहता है, मैं उस की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं वह जो कुछ कहता है, वह ठीक है। उन्होंने संसद् सदस्यों की बात को झुठलाने की कोशिश की, अपने अधिकारियों को सच्चा कहा और उनके द्वारा दी गई सूचना की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हुए।

इस प्रतिवेदन से यह भी मालूम होता है कि यहां की एक्सीक्यूटिव, मैजिस्ट्रेसी और पुलिस अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं और यह सरकार तथा गृह मंत्रालय किस प्रकार से उन पर पर्दा डालते हैं। इस सदन के एक माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया, उनको थाने में रखा गया, लेकिन उन की गिरफ्तारी से साफ इन्कार किया गया। माननीय सदस्य स्वयं सत्याग्रह करने के लिए गए, उन्होंने अपने आप को सत्याग्रह के लिए पेश किया। इस के लिये उनको दो घंटे की सजा मिले या छः महीने की, इस बारे में कोई एतराज नहीं है। यह प्रश्न न तो समिति के सामने था और न सदन के सामने प्रश्न केवल इतना था कि जब उन को गिरफ्तार किया गया या सजा दी गई तो उस की सूचना आप को और इस सदन को देनी चाहिए थी, लेकिन यहां के हाकिम इतने मगरूर हैं, उन में इतना घमंड है कि वह नियमों के अनुसार इस के बारे में इस सदन को और उस के अध्यक्ष महोदय को सूचना देने के लिए तैयार नहीं हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस किस्म का पहला मौका नहीं है। दिल्ली में जो न्याय-व्यवस्था है, जो ला एंड आर्डर सिचुएशन है, उस के ऐसे कई उदाहरण इस से पहले भी हमें मिले हैं कि लोगों के साथ इस प्रकार का अनुचित व्यवहार किया गया है। आप को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दिल्ली के महापौर (मेयर), यहां के चीफ एक्सीक्यूटिव कौंसिलर, दिल्ली कार्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और इस सदन के कई माननीय सदस्य आज से चार छः महीने पहले दफा 107 और 151 के मातहत गिरफ्तार किये गए, जिस के अन्तर्गत गुंडों को गिरफ्तार किया जाता है। जब लोग नकद रुपया ले कर उन की जमानतें देने के लिए गए, तो मैजिस्ट्रेटों ने उन की जमानतें नहीं लीं। यहां की मैजिस्ट्रेसी किस तरह से काम करती है, दिल्ली की हाई कोर्ट ने उस की कड़ी आलोचना की है। हम ने आशा की थी कि उस आलोचना के बाद यहां की मैजिस्ट्रेसी और एक्सीक्यूटिव में कुछ सुधार होगा। लेकिन अब गृह मंत्री ऐसे आदमियों को पनाह देने के लिए तैयार

हैं, जो इस सदन का और आप का अपमान करते हैं, तो वहां कोई भी सुधार होने की आशा नहीं है

जैसा कि मैं ने कहा है, गृह मंत्री ने जिला अधिकारियों की कार्यवाही और उन के कथन की पूरी जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि माननीय सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन इस कमेटी ने यह फैसला दिया है कि माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया था। इस सूरत में यह सदन गृह मंत्री की भर्त्सना करे और मंत्री महोदय को इस सदन में आ कर अपने उस वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्षमा-याचना करनी चाहिए।

मैं आप के द्वारा गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस बारे में अपनी पोजीशन स्पष्ट करें।

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the First Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 22nd May, 1967, be taken into consideration."

Now, Shri Shrichand Goel. He may speak for about two minutes now and continue his speech after lunch.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): Let him start his speech after lunch.

Mr. Speaker: All right. We shall now adjourn for lunch and let him begin his speech after lunch.

12.58 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the Clock.

[SHRI C. K. BHATTACHARYYA *in the Chair*]

MOTION RE. FIRST REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES—*contd.*

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : माननीय सभापति महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में जो विशेषाधिकार समिति बनी थी, उसका पहला प्रतिवेदन अब इस सदन के सम्मुख है। जिस योग्यता और परिश्रम के साथ इस प्रश्न पर विचार कर के इस समिति ने अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र की संसदीय प्रणाली में लोक सभा और उसके सदस्यों का विशेष स्थान है। जहां कहीं या जब कभी भी उनके विशेष अधिकारों पर किसी प्रकार का जाने में या अनजाने में कोई आक्रमण हो, उस समय इस सदन का कर्तव्य है कि सदन के सम्मान और उसकी गरिमा की रक्षा के लिये विशेष चिन्ता कर के, तथा विशेष जागरूक रह कर उन अधिकारों की रक्षा करे। जिस समय यह प्रश्न इस सदन के सामने आया था कि क्या इस सदन के सम्माननीय सदस्य की गिरफ्तारी पर इस सदन के अध्यक्ष तथा इस सदन को उसकी जानकारी दी गई अथवा नहीं दी गई तो क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न है अथवा नहीं। मैं यह समझता हूं कि आज की इस परिपाटी के अनुसार, इस सदन की परम्पराओं के अनुसार और संसार के सभी लोकतन्त्रीय देशों के अन्दर जो स्वस्थ परम्परायें हैं उनके अनुसार यह आवश्यक है कि किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी होने पर उसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी सदन को और उसके अध्यक्ष को मिलनी चाहिये। लेकिन वह जानकारी चूंकि दी नहीं गई, इसलिये मैं समझता हूं कि वह हमारे विशेषाधिकार पर एक आक्रमण था। लेकिन जिस समय यह प्रश्न इस सदन के सामने उपस्थित हुआ, हमारे गृह मंत्री ने अपने अधिकारियों की जानकारी के आधार पर यह विचार देने का प्रयत्न

[श्री श्रीचन्द गोयल]

किया कि किसी भी सम्मानीय सदस्य के अधिकारों का यहां पर प्रश्न नहीं है। चूंकि वे स्वयं पुलिस के ट्रक के अन्दर दाखिल हुए थे उनको पुलिस या पुलिस अधिकारियों की तरफ से बन्दी नहीं बनाया गया था, गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन इस समिति ने बड़ी योग्यता के साथ सबकी गवाहियां लीं सम्माननीय सदस्य स्वामी ब्रह्मानन्द जी की भी गवाही हुई तथा इस प्रकार से जितने भी पुलिस अधिकारी इस घटना से सम्बन्धित थे, उनकी भी गवाहियां ली गईं। उसके नतीजे के आधार पर वह समिति इस निर्णय पर पहुंची कि बाकई स्वामी ब्रह्मानन्द जी को गिरफ्तार किया गया या कम से कम उनको डिटेन अवश्य किया गया था, उनकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था।

स्वामी ब्रह्मानन्दजी ने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि वह धारा 144 को तोड़ कर सत्याग्रह कर रहे थे और उनको पुलिस अधिकारियों ने रोका था और कहा था कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। उनको शुरू में पुलिस के ट्रक में बैठा कर तथा बाद में जीप के द्वारा पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया और वहां पर उनका नाम व पता आदि नोट किया गया। तीन-चार घन्टे की इस कार्यवाही के बाद उनको मुक्त किया गया। मैं अपनी सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इस सदन के माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों का प्रश्न है वहां पुलिस अधिकारियों को उनके साथ जो साधारण पुलिस के हथकण्डे हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिये था। लेकिन इस केस में इस प्रकार के हथकण्डे जो पिछली तारीख में इस्तेमाल होने थे, वे इस्तेमाल किये गये और यह कहा गया कि स्वामी ब्रह्मानन्द स्वयं पुलिस के ट्रक में दाखिल हुए, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस सदन के माननीय सदस्यों के साथ व्यवहार करने का ताल्लुक है उनका और विशेष कर इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी प्रकार की कोई गलतफहमी और भ्रान्ति पैदा करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। हमारे गृह मंत्री के पास दिल्ली पुलिस के जो अधिकार हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए सीधे रूप से इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। इस लिये उनका कर्तव्य था कि बगैर इस मामले की जांच कराये बगैर इस मामले की गहराई में गये हुए, इस सदन में इस प्रकार के विचार न देते, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का विचार देने का प्रयत्न किया।

माननीय सभापति महोदय मैं इस बात की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां के जो डिप्टी कमिश्नर श्री टण्डन साहब हैं, उन्होंने समिति की चार बैठकों के बाद भी केस को इस ढंग से पेश करने की कोशिश की—उन्होंने कहा कि यदि समिति यह समझती है कि सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तब वह क्षमा मांगने के लिये तैयार हैं। उन्होंने जिस तरह से एक कहावत है कि मेंगनी डाल कर दूध देने की कोशिश की, लेकिन इस समिति के योग्य और माननीय सदस्यों ने फिर से उनसे कहा कि आप इस बात को स्पष्ट बताइये कि आप अनकन्डीशनल क्षमा मांग रहे हैं या कन्डीशनल, तब उन्होंने इस समिति के सदस्यों का रुख देख कर अनकन्डीशनल एपोलोजी टेन्डर की, बिना किसी शर्त के उन्होंने क्षमा याचना की।

मैं समझता हूं कि आज शिक्षा लेनी चाहिए पुलिस कर्मचारियों को इस घटना से पुलिस के अधिकारियों से भी और गृह मंत्री से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस मामले की और गहराई में जाये बगैर सदन को गलत विचार देने की

कोशिश की है और इस कारण उनको सदन के सामने आज क्षमा मांगनी चाहिए और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको इस घटना से शिक्षा लेनी चाहिये। तथा जहां तक इस सदन के माननीय सदस्यों के साथ व्यवहार करने का ताल्लुक है उस से वह जो साधारण पुलिस का रवैय्या है तथा जो साधारण पुलिस के हथकंडे हैं वह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। बस मुझे इस वक्त इतना ही कहना है।

Shri A. N. Mulla (Lucknow): Mr. Deputy-Speaker, I had the honour of being a Member of the Privileges Committee and the decision reached is one in which I had concurred. I, therefore, feel that some Members might have an idea that because I have already expressed an opinion, whatever I will say here will be coloured by the opinion which I have already expressed. Let me assure the House that I shall place before it only some legal aspects as to how evidence should be assessed and I will not enter into the question whether the view taken by the Home Minister was the correct view or the view taken by the Privileges Committee was the correct view.

Shri B. Barua (Jorhat): Sir, on a point of order. It is a convention of the House that whenever a Member of a committee like the Privileges Committee has concurred in the report, he does not speak in the House. He says he was a Member of that Committee. Are we going to make a departure from that practice?

Mr. Chairman: In connection with the motion brought up for consideration of the report, he is speaking.

Shri B. Barua: Is it correct for a Member of a Committee to make a speech here for or against a report like that?

Mr. Chairman: I find nothing wrong in it.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur): He has already expressed his views in the Committee. Is it not correct that he should speak about them in the House?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): The report is a unanimous one. What Mr. Barua and Sardar Saigal say—that is also the correct procedure. Though Mr. Mulla was a Member of the Committee, he is perhaps not going to express any contrary opinion. Therefore, I do not think that there is anything wrong in his speaking.

Mr. Chairman: Let Mr. Mulla continue.

Shri A. N. Mulla: I was saying that there was a marked difference between the assessment of facts as given in the note prepared by the Home Minister and the conclusions reached by the Committee on Privileges. The point on which I want to lay stress is that this difference can be accounted for by the reason that the approaches made by the two groups were entirely different. I have been associated with judicial work for sometimes. I have always been of the opinion that when it comes to assessment of evidence, there are only two approaches open to a person. One is that you make a credulous approach and believe everything that is being said by a party. The other approach is the approach of reason, when you test the statement made by a person in the light of the human conduct and human experience, and then come to your own conclusions as a man of prudence and caution whether this version can be accepted or not. It is the opinion of the Committee that the Home Minister depended too much upon the version presented before him by the district authorities and he did not apply the test of reason or the approach of prudence and caution to whatever was placed before him. When the Committee met, naturally the Committee approached the question from a different angle.

[Shri A. N. Mulla]

The evidence came before it; it sifted it; it naturally preferred the probable over the improbable; reasonable over the unreasonable. It was impossible for the Committee to accept that Swami Brahmanand not only voluntarily boarded a van which was standing over there but then after some lapse of time he made up his mind voluntarily to get down from that van and boarded another jeep and then he called some police constable to accompany him and take him to the police station and then the police constable obliged him by boarding the van along with him and then got down at some place in between. It was only a credulous man who could have accepted this type of story, and therefore, because this story could not be accepted, it became obvious that it was the police agency which was responsible for taking Swami Brahmanand into detention at some stage and take him to the police station. The very fact that his name was taken down in the police papers by itself indicates that he was taken in some sort of detention, for the names of the persons who are not detained are not taken down in the police papers.

It is not necessary to dilate on this point. I have put certain questions to the District Magistrate and he agreed with me that if Swamiji did not invite the police constable himself and was taken by the police to the thana, then it would amount to detention, and as we have accepted that version, it is clear that Swamiji was detained and was taken to the thana.

So, all that I would like to stress here at this stage is that repeatedly the authorities take a wooden view of the facts presented before them because they rely too much upon the evidence of these police officers who, in order to cover up their own failings, their own mishandling of the situation, give a garbled version. This should be tested and analysed and then a statement should be made before the House. I think the Home Minister failed to make that sort of statement. I therefore will suggest that the conclusions reached by the Committee should be accepted by this House and with your permission I will move this motion, namely,—

Mr. Chairman: That will come later. After the House disposes of the present motion, then, he can move his motion. I shall call him at that time after this motion is disposed of.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, इस प्रीविलेज कमेटी की रिपोर्ट के बारे में दो मत नहीं हैं। यह सर्वसम्मति से पास की गई रिपोर्ट है और मैं समझता हूं कि हाउस इसी रूप में इसको स्वीकार करेगा परन्तु मैं एक दो बातों की ओर गृह मंत्रालय का ध्यान खींचना चाहता हूं। दिल्ली प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका जो रवैया जनता के साथ या ऐसे मामलों के साथ है अगर आप यह रिपोर्ट देखेंगे और उसके अन्दर जो कुछ क्रास एग्जामिनेशन जस्टिस मुल्ला ने किया है या मैं ने किया अथवा औरों ने किया उसको देखें तो आपको पता लगेगा कि किस कैजेलियर ढंग से प्रमुख अधिकारी जनता के साथ डील करते हैं।

एक बात जिसकी ओर मैं गृह मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहूंगा यह है। स्वामी ब्रह्मानन्द ने यह कहा था कि हम को थाने में ले गये और वहां पर हमारे नाम लिखे गये। अब यह एक स्टेटमेंट आफ फैक्ट है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कुछ और लोगों ने कहा कि नाम नहीं लिखे गये। इस प्रकार से एक जो स्टेटमेंट आफ फैक्ट हैं उसके अन्दर एक संसद सदस्य को और एक ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत सम्मानित है, झुठलाया जाता है। अगर ऐसा व्यवहार एक संसद सदस्य के साथ किया जा सकता है तो फिर आम जनता के साथ क्या किया जाता होगा इसको आप सोच सकते हैं।

इसी प्रकार से जो पुलिस इन्स्पेक्टर गवाही देने आये उन्होंने इस प्रकार से बातें की जिस प्रकार से जो टाउट तैयार कर के लाये जाते हैं वह करते हैं या जो ट्यूटर्ड आदमी होते हैं वह गवाही देते हैं। और मुझ को वहां पर कहना पड़ा कि क्या इसी प्रकार से उनको गवाही देने की बात सिखलाई जाती है। यह ऐसी चीजें हैं जिन पर गृह-मंत्रालय को विचार करना चाहिये। आज देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या अव्यवस्था बढ़ रही है उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो अधिकारी हैं, जो पुलिस आफिसर्स या दूसरे आफिसर्स हैं, उनका जो रंग है उससे जनता में विश्वास पैदा होने के बजाय अविश्वास पैदा होता है।

इसलिये मैं चाहूंगा कि इस रिपोर्ट को यथावत् स्वीकार कर लिया जाय, परन्तु इस रिपोर्ट में जो भी बातें दी हुई हैं उनके प्रकाश में यह मंत्रालय जरूर ध्यान दे।

Mr. Chairman: I may point out that under the rules,

> "such debate shall not refer to the details of the report further than is necessary to make out a case...."

Shri P. Ramamurti (Madurai): I do not want to go into the details. A Member of the House had stated on the floor of the House that he had been arrested or detained. When such a serious allegation was made by a Member, it was incumbent on the Home Minister to give the consideration that was due to it and just not rely upon some cavalier-fashioned enquiry that was conducted by the officials concerned. Mr. Mulla had dealt with that aspect. The District Magistrate and the other officials went on enquiring all and sundry, but they did not enquire from the key person who had first reported to the Speaker that such and such a person had been arrested. He was a witness to the whole thing, but he was not enquired. In fact, I put a specific question about that. This is the sort of enquiry on the basis of which a report is made to the House and the Home Minister relying upon that kind of report, in his speech indulges in all sorts of innuendoes against the member concerned. If this is the treatment meted out to a Member of Parliament, we can understand the kind of treatment meted out to the ordinary people who are subjected to police harassment.

At least in this particular case the Home Minister should have the decency to apologise to the House for having made that kind of statement in which innuendoes were made against an hon. Member of this House. That is the least that is expected of them. They will not lose anything by it; on the other hand, their prestige will go up. But if they do not want that and if they want to go down as people who stand on wrong ideas of prestige and stick to their own position, to hell with them. Nobody can save them. All I want them to understand is, at least hereafter they should send a directive that a judicial frame of mind must be brought to bear on such questions and they should find out whether all the persons who can give evidence have been enquired. Otherwise, the concerned officials against whom the whole enquiry is there make up a report and naturally they justify whatever they have done. Therefore, it should not be a white-washing inquiry for the purpose of justification of whatever the government officials, the police officials or the district officials have done. There must be a real inquiry. This is the lesson that anybody will have to draw from this Committee's report. I hope this Government also will draw that lesson and in future at least it will behave properly.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): Sir, I am sorry that some of the hon. Members have

[Shri Vidya Charan Shukla]

chosen to bring politics in this matter. This is a matter between the Members of this House and the Administration as such and, as we have said earlier, we are as zealous to protect the rights of Members of this House as anybody could be. The Committee of Privileges which went into this question has not said any such thing. They went into several details and they have chosen not to say anything about it. They found nothing to say against the Home Minister or the Home Ministry. Therefore, I would request the House to accept the findings of the Committee as given in the report and not import politics into this matter. This has now been amicably settled and we accept the report of the Committee.

Shri Bal Raj Madhok: I think the hon. Minister has misunderstood what we said. We never wanted to bring politics into the matter. What we wanted to say was that certain things came to our notice. We did not want to refer to them in the conclusion of the Privileges Committee report. But we want to bring those things before this House for the consideration of the Home Ministry so that it may think about this matter and see that those certain things which came to light are not repeated. This we did in your interest, for your benefit and no politics has been brought in here.

Shri P. Ramamurti: Obviously, Sir, the speech of the Home Minister was not referred to this Committee. It was not their job. Their job was, in that particular matter, not what happened, not what he spoke. (*Interruptions*).

Mr. Chairman: The time fixed by the Speaker for this motion is exhausted. I shall now put the motion to the House. The question is:

> "That the First Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 22nd May, 1967, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Shri A. N. Mulla: With your permission, Sir, I beg to move:

> "That this House agrees with the First Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 22nd May, 1967."

Mr. Chairman: The question is:

> "That this House agrees with the First Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 22nd May, 1967."

The motion was adopted.

Shri Vasudevan Nair (Peermade): Sir, before you proceed with the next item on the Agenda—the Railway Budget—I would like to bring to your notice that many Members of this House, yesterday, gave notice, about correcting answers given in the House. Sir, very wrong and false statements have been made by the Minister of Food on the floor of this House as well as outside and he is continuing to make such statements on the food situation and supplies to States. We would like to know when that statement will be made and when an opportunity will be given to us?

Mr. Chairman: I understand it is under the consideration of the Speaker and he has referred it to the Minister of Food.

Shri Vasudevan Nair: We want to convey that it is a very serious matter

Mr. Chairman: Nobody in the House disputes its seriousness, but the matter is under the consideration of the Speaker and when he has considered it he will bring it before the House.

श्री मधु लिमये : केरल और बिहार के बारे में भी।

Mr. Chairman: All those questions are under his consideration.

Shri E. K. Nayanar (Palghat): I have also given notice of it.

Mr. Chairman: All the notices are with him. (*Interruption*).

14.30 hrs.

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

Mr. Chairman: The House will now take up general discussion of the Railway Budget.

Shri Rajaram (Salem): Mr. Chairman, I thank you for giving me an opportunity to participate in the general discussion on the railway budget. The railway budget was presented to the House on the 22nd of this month. On the 21st of this month a big accident took place in my part of the country, near Kuppam. Nearly 69 people have died because of this accident. There is a joke about the railways that even though they do not contribute anything else to the nation, they contribute in solving the population problem by killing people in accidents. That joke has become a reality now. Though we were coming across so many accidents in this part of the country, so far as the southern side was concerned there were no major accidents until this accident at Kuppam. I hope that the Railway Ministry will come forward to do justice to the people who have been affected by that accident.

In this budget the rates have been increased on a number of items. If the railway policy for the Third Plan period is reviewed it will be found that there is hardly any year in which increase in passenger fares or freight rates has not been effected. For instance, in 1960-61, the last year of the Second Plan, there was a surcharge of 5 paise per rupee on freight rates on coal and other items. This was followed by what was called a marginal adjustment in freight rates in the year 1961-62. Then, in the year 1961-62, again the basic rates chargeable for goods traffic were increased by 50 paise per ton and passenger fares were increased by 10 to 15 per cent. Then, in the year 1963-64 a surcharge of 10 per cent on parcels was levied. In the year 1964-65 a surcharge of 2 per cent on freight rates was levied. In the year 1965-66 there were increased passenger fares and freight rates over 25 items. In the year 1966-67 there was no increase in passenger fares or freight rates because it was an election year. In the present railway budget the rates have been increased on so many items. For instance, in South India they were selling a railway guide for 30 paise. Now the price has been raised to 50 paise. The price of platform tickets has been raised by 50 per cent, the cost of reservation of tickets by 100 per cent and the cost of third class tickets by 12½ per cent.

For your information, we, the DMK party, are running a Government at the State level. In the olden days, members of the opposition used to give comparison with foreign countries. Now I want to give a comparison between the State and the Centre. In our State, the DMK ruling party has got a Transport Minister called Karunanidhi. We affectionately called him as Kalaignar Karunanidhi. He has reduced the bus fares by 1 paisa per one mile. He has announced it only last month. After this reduction was announced, he has gained more profits from bus transport. Of course, because of the Morarji budget it may be raised sooner or later, but that is an entirely different matter. When on one side the non-Congress Ministries, non-Congress Governments, are trying to bring down the price level, are trying to bring down the ticket rates to do justice to the common pepole, the down-trodden, on the other side, the railways both in the Third Plan period and now in the Fourth Plan are increasing the rates in such a way that when there is